संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा और चयन प्रक्रिया में दोष

1582. **श्री शरद यादव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा तथा चयन प्रक्रिया में दोष उत्पन्न हो गये हैं ;

(ख) क्या सरकार उसमें सुधार करने का विचार रखती है ;

(ग) क्या संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में हिन्दी को अपनाने के लिए इस वर्ष प्रयास किये गये थे ;

(घ) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या हैं ; और

(ङ) यदि उपर्युक्त भाग (ग) का उत्तर "ना" हो तो उसके कारणों का ब्यौरा क्या हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) सरकार के ध्यान में ऐसी कोई बात नहीं आई है जिस से यह पता चलता हो कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा तथा चयन प्रक्रिया में कोई त्रुटियां उत्पन्न हो गयी हैं । आयोग अपनी प्रक्रियाओं तथा अपनी परीक्षाओं की योजनाओं/पाठयक्रमों की स्वतः तथा सुझावों के प्राप्त होने पर भी सतत रूप से पुनरीक्षा करता रहता है ।

(ग) से (ङ) आयोग पहले ही अपनी कुछ परीक्षाओं जैसे कि सिविल सेवा परीक्षा, आशुलिपिक परीक्षा तथा सहायक ग्रेड परीक्षा में या तो प्रश्न पत्रों के उत्तर के लिए माध्यम के रूप में अथवा प्रश्न पत्रों के मुद्रण के माध्यम से हिन्दी के प्रयोग की अनुमति दे रहा है । आयोग द्वारा दिसम्बर, 1987 में ली गई अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक ग्रेड "ख" (ग्रेड-1) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कुछ प्रश्न पत्रों के प्रश्नों को अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों भाषाओं में मुद्रित किया गया था ।

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग

1583. **श्री शरद यादव :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में कितने लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे थे ;

(ख) गरीबी की रेखा के निर्धारण का क्या मानदण्ड है ;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी को दूर करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गये है तथा उनका ब्यौरा क्या हैं ; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष में विभिन्न राज्यों में कितने-कितने व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना लागू करते समय गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के आकलन के लिए उपलब्ध आंकडे वर्ष 1983-84 के थे जोकि पारिवारिक उपभोक्ता व्यय से संबंधित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 38वें चक्र के परिणामों के आधार पर तैयार किए गए थे । इन अनुमानों के आधार पर देश में 2710 लाख व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे थे जोकि कुल जनसंख्या का 37.4 प्रतिशत है ।

(ख) गरीबी की रेखा निर्धारित करने की मुख्य कसौटी कैलोरी का उपभोग है । योजना आयोग द्वारा गठित (1979) "न्यूनतम आवश्यकता और प्रभावी उपभोग मांग" से संबंधित कृतक वल ने 1973-74 की कीमतों पर ग्रामीण क्षेत्रों में 49.09 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 56.64 रुपए के मासिक व्यय के अनुसार गरीबी की